19/07/2024

आकाशवाणी ईटानगर

अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। पहले दिन सदन में तीन विधेयक पेश किए गए। जिनमें Arunachal Pradesh Public Examination (भर्ती में अनुचित साधनों को रोकने के उपाय) विधेयक 2024, The Arunachal Pradesh Amending Bill 2024 और बालूपारा, तिराप, सदिया सीमांत क्षेत्र झूम भूमि विनियमन (संशोधन) विधेयक 2024 शामिल हैं। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष तेसाम पोंगते ने चालू सत्र के लिए अध्यक्षों की सूची की घोषणा की। सदस्यों में डॉ. मोहेश चाई, हायेंग मांगफी, त्सेरिंग ल्हामू और मोपी मिहू शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट आगामी 24 जुलाई को उपमुख्यमंत्री चाउना मेंन द्वारा पेश किया जाएगा, जो वित्त विभाग भी संभाल रहें हैं। 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के दूसरे विधानसभा सत्र में छह बैठकें होंगी जो आगामी छब्बीस जुलाई को सम्पन्न होगी। प्रस्ताव पेश करते हुए विधायक मुचू मिथी ने कहा कि, अरुणाचल प्रदेश सरकार पिछले आठ वर्षों से संसाधनों के समान वितरण पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों के लाभ के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य की योजनाओं के साथ जोड़ रही है। श्री मिथी ने कहा कि, राज्यपाल के भाषण का एकमात्र लक्ष्य लोगों का कल्याण है। प्रस्ताव का समर्थन करते हुए विधायक जिक्के ताको ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पर बहुत काम किया है और ऐसा करने में वह काफी हद तक सफल रही है।

चर्चा में भाग लेते हुए विधायक निख कामिन ने राज्य सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर और अधिक जोर देने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा सुविधाओं के साथ-साथ विभागों में मानव शक्ति की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सत्र में भाग लेते हुए विधायक थांगवांग वांगहाम ने कहा कि, राज्य में अधिक अवसर पैदा करने के लिए पर्यटन की संभावनाओं का दोहन किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य में सामाजिक लेखा परीक्षा प्रणाली लागू करने का भी प्रस्ताव और सुझाव दिया।

0000000000000000000

सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं और अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बजट सत्र के पहले दिन आज राज्य विधानसभा में अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों को रोकने के उपाय) विधेयक, 2024 पेश किया। प्रस्तावित कानून में कारावास और जुर्माने की सज़ा, उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षाओं में बैठने से रोकने के साथ-साथ संपत्ति की ज़ब्ती के सख्त प्रावधान हैं। ऐसे अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान भी विधेयक में शामिल किया गया है। राज्य विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक की कुप्रथा पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार की यह बहुत अच्छी पहल है।

उन्होंने कहा कि एक बार विधेयक पारित हो जाने के बाद कोई भी इस तरह की गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। श्री खांडू ने आगे कहा कि अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों को रोकने के उपाय) विधेयक, 2024 राष्ट्रीय कानून, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 से अधिक कठोर है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा और अभ्यर्थी इस कानून से काफी संतुष्ट होंगे।

0000000000000000000

अरुणाचल प्रदेश के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री और पूर्व एपीसीसी अध्यक्ष तालो मुगली का गत गुरुवार को लंबी बीमारी के बाद कामले जिले के रागा स्थित उनके आवास पर सड़सठ साल की उम्र में निधन हो गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. परनाइक ने शोक व्यक्त करते हुए पंचायत सदस्य, विधायक और मंत्री के रूप में दिवंगत मुगली की व्यापक सेवा की प्रशंसा की है और शोक संतप्त परिवार के लिए प्रार्थना की। इस बीच, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और सामुदायिक कल्याण और राज्य के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद किया है।

0000000000000000000

Lohit Youth Library Movement, बांबूसा लाइब्रेरी तेजू की वरिष्ठ स्वयंसेवक केसेलो तायांग को गत गुरुवार मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में हार्दिक सराहना मिली।

इस अवसर पर गेस्ट स्पिकर के रूप में बोलते हुए उन्होंने “हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सुशासन” पर सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भाषा समुदायों के लिए शिक्षा को बढ़ाने में स्वैच्छिकता की भूमिका पर एक आकर्षक व्याख्यान दिया। सुश्री तायांग ने लोहित युवा पुस्तकालयों के साथ 16 वर्षों के अनुभव से लाभ उठाते हुए सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और युवा समूहों के बीच सहयोग पर जोर दिया। इस बीच, भारत सरकार के संयुक्त सचिव गृह, प्रशांत लोखंडे, ने भी केसेलो और लोहित युवा पुस्तकालय स्वयंसेवकों की उनकी टीम की सराहना की और अरुणाचल में सभी कार्यकर्ताओं को अपनी शुभकामनाएं दीं।

0000000000000000000

पापुम पारे के लिए क्षेत्रीय सीमा विवाद समिति के नवनियुक्त सदस्यों की एक समीक्षा बैठक आज यूपीया में हुई, जिसमें पिछली सीमा समिति द्वारा किए गए जमीनी कार्यों का मूल्यांकन और वर्तमान स्थितियों का आकलन किया गया। साथ ही, असम और अरुणाचल के बीच सीमा मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए रणनीति तैयार की गई। इस अवसर पर बोलते हुए, 14 दोईमुख विधायक नाबाम विवेक ने सीमा चुनौतियों से निपटने के लिए सटीक एवं संपूर्ण जानकारी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से अगस्त 2024 तक क्षेत्रीय आकलन पूरा करने का आग्रह किया। सितंबर में असम के समकक्षों के साथ बैठक का प्रस्ताव रखा। इस बीच, राज्यसभा सांसद नाबाम रेबिया ने नामसाई घोषणा के तहत असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर जानकारी दी।

उन्होंने हितधारक परामर्श की आवश्यकता पर बल दिया। समिति में अध्यक्ष एवं राज्य के भूमि प्रबंधन मंत्री बालो राजा और सदस्य 14 दोईमुख विधायक नाबाम विवेक, राज्यसभा सांसद नाबाम रेबिया, पापुम पारे उपायुक्त जिकेन बोम्जेन और एसपी तारू गुसार शामिल हैं।

0000000000000000000